



GK/GS का महा संग्राम

POLITY

आपातकालीन प्रावधान (EMERGENCY PROVISIONS)

हमारे **TOPIC EXPERT** के साथ

देखें शाम 07:00 बजे



LIVE

BY GS GURU



Emergency Provisions

आपातकालीन प्रावधान



GS/ GK का महासंग्राम



Art 352 to Art 360

संविधान

• The Government of India Act 1935 served as the inspiration for the emergency provision in the Indian Constitution. Articles 352 through 360 of Part 18 of the Indian Constitution discuss emergency measures and deal with emergency situations in India. A state of emergency transfers all authority to the central government.

• भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपायों पर चर्चा करते हैं और भारत में आपातकालीन स्थितियों से निपटते हैं। आपातकाल की स्थिति सभी अधिकार केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर देती है।



GS/ GK का महासंग्राम



- Under Part 18 of the constitution, where particular articles have been drafted, the emergency provisions of the Indian constitution are mentioned. An essential supplement that discusses the many emergency scenarios that can arise in India is the emergency article.
- संविधान के भाग 18 के तहत, जहां विशेष अनुच्छेदों का मसौदा तैयार किया गया है, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। एक आवश्यक पूरक जो भारत में उत्पन्न होने वाले कई आपातकालीन परिदृश्यों पर चर्चा करता है वह आपातकालीन लेख है।



GS/ GK का महासंग्राम



National
Emergency

• Article 352 was added to the constitution to address emergency situations brought on by external threats like war or armed insurrection.

President
Rule

• Article 356 addressed the President's declaration of an emergency as a result of the broken constitutional mechanism.

• Article 360 – Because the nation's financial stability was in jeopardy, this article was added to deal with the financial emergency. Dr. B.R. Ambedkar added it considerably later.

Vibh

• युद्ध या सशस्त्र विद्रोह जैसे बाहरी खतरों से उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए संविधान में अनुच्छेद 352 जोड़ा गया था।

• अनुच्छेद 356 में टूटे हुए संवैधानिक तंत्र के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को संबोधित किया गया था।

• अनुच्छेद 360 - क्योंकि देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में थी, इसलिए वित्तीय आपातकाल से निपटने के लिए यह अनुच्छेद जोड़ा गया था। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इसे काफी बाद में जोड़ा।



GS/ GK का महासंग्राम



- The purpose of the emergency provisions is to ensure that the country is prepared for emergencies and that the necessary actions may be performed should they arise. These emergency clauses in the Indian Constitution were included in an effort to safeguard the nation's integrity, sovereignty, and general security as well as to provide the necessary framework for the President to declare a national emergency.
- आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश आपात स्थिति के लिए तैयार है और आपात स्थिति उत्पन्न होने पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। भारतीय संविधान में इन आपातकालीन धाराओं को देश की अखंडता, संप्रभुता और सामान्य सुरक्षा की रक्षा के साथ-साथ राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करने के प्रयास में शामिल किया गया था।



Administrative Relations

- The distribution of legislative authority has resulted in a shared executive branch between the federal government and the states.
- Article 256 to 263 of the constitution deals with the administrative relation between the Centre and States.

प्रशासनिक संबंध

- विधायी प्राधिकार के वितरण के परिणामस्वरूप संघीय सरकार और राज्यों के बीच एक साझा कार्यकारी शाखा बन गई है।
- संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध से संबंधित है।



GS/ GK का महासंग्राम



- Three sorts of emergencies have been identified based on the three articles that were created to address emergency situations, as shown below:

- Art 352 a) National Emergency → राष्ट्रीय आपातकाल
- Art 356 b) Constitutional Emergency/State Emergency - संवैधानिक आपातकाल
- Art 360 c) Financial Emergency → वित्तीय आपातकाल

- आपातकालीन स्थितियों को संबोधित करने के लिए बनाए गए तीन लेखों के आधार पर तीन प्रकार की आपात स्थितियों की पहचान की गई है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

- a) राष्ट्रीय आपातकाल
- b) संवैधानिक आपातकाल/राज्य आपातकाल
- c) वित्तीय आपातकाल



GS/ GK का महासंग्राम



National Emergency (Art 352)

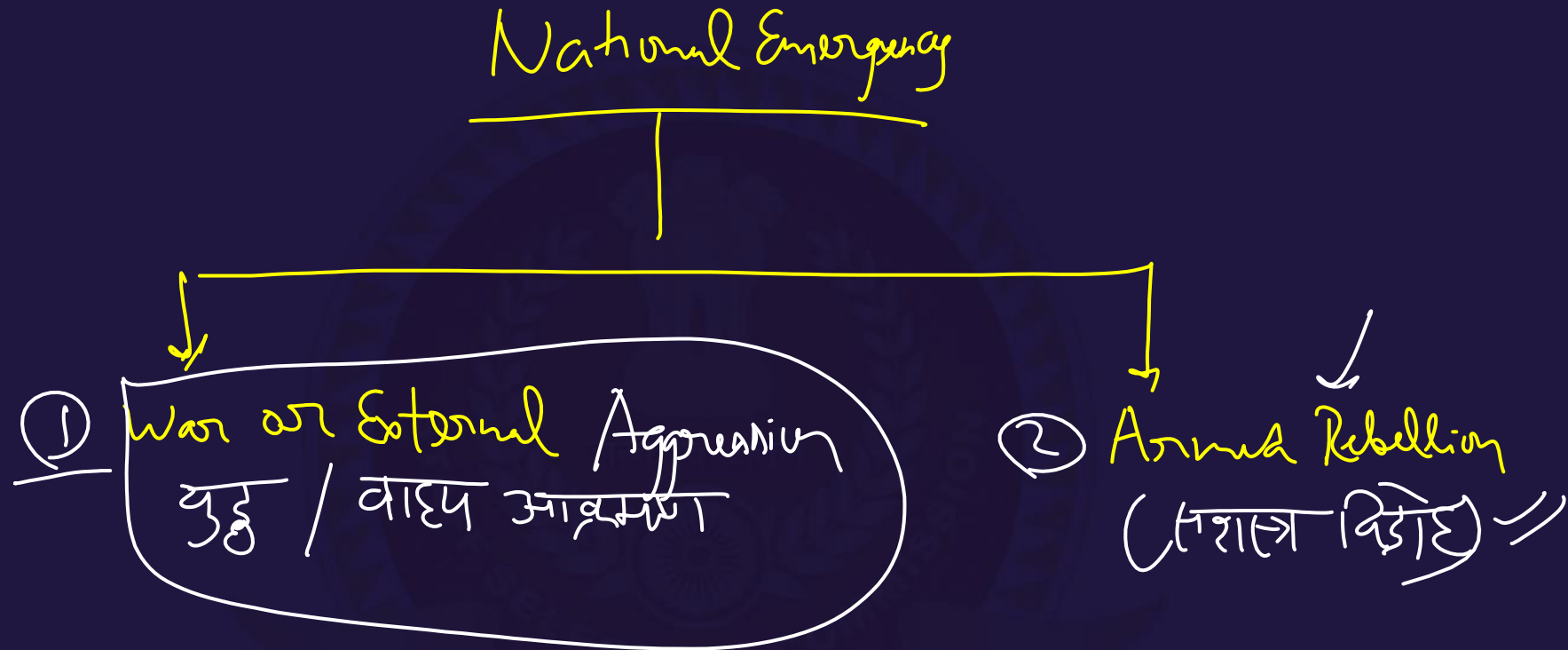
- When the security of the country is threatened by external or internal elements like war, armed revolt, or other hostile acts, a National Emergency is declared under Article 352 of the Indian Constitution. An “External Emergency” is what it is known as when a National emergency is declared as a result of an external threat.

राष्ट्रीय आपातकाल

- जब देश की सुरक्षा को युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या अन्य शत्रुतापूर्ण कृत्यों जैसे बाहरी या आंतरिक तत्वों से खतरा होता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। "बाहरी आपातकाल" उसे कहा जाता है जब किसी बाहरी खतरे के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है।



GS/ GK का महासंग्राम





National Emergency

On the other hand, it is referred to as an “Internal Emergency” if such an emergency is declared as a result of a “armed rebellion”. Even prior to an incident occurring, the President has the authority to proclaim a national emergency. When India was at war with China in 1962, the first National Emergency was established. Indira Gandhi then proclaimed an additional “Internal Emergency” at that time.



राष्ट्रीय आपातकाल

- दूसरी ओर, इसे "आंतरिक आपातकाल" कहा जाता है यदि ऐसा आपातकाल "सशस्त्र विद्रोह" के परिणामस्वरूप घोषित किया जाता है। किसी घटना के घटित होने से पहले ही राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। 1962 में जब भारत चीन के साथ युद्ध में था, तब पहला राष्ट्रीय आपातकाल स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी ने उस समय एक अतिरिक्त "आंतरिक आपातकाल" की घोषणा की।



Constitutional Emergency or President's Rule

- Article 356 specifically addresses the situation of a “state emergency,” sometimes known as a “constitutional emergency” because it denotes a breakdown in the nation’s constitutional framework. According to Article 356 of the Indian Constitution’s emergency clause, the central government performs all governmental duties.

संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन

- अनुच्छेद 356 विशेष रूप से "राज्य आपातकाल" की स्थिति को संबोधित करता है, जिसे कभी-कभी "संवैधानिक आपातकाल" के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह देश के संवैधानिक ढांचे के टूटने को दर्शाता है। भारतीय संविधान के आपातकालीन खंड के अनुच्छेद 356 के अनुसार, केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्तव्यों का पालन करती है।



Financial Emergency

- In order to take control of the situation and prevent panic among the populace while the nation is experiencing a financial crisis, the President of India may declare an emergency. Article 360, which allows the application of the emergency provisions, can be used to address a financial emergency.



वित्तीय आपातकाल

- जब देश वित्तीय संकट का सामना कर रहा हो, तब स्थिति को नियंत्रित करने और जनता के बीच घबराहट को रोकने के लिए, भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 360, जो आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है, का उपयोग वित्तीय आपातकाल को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है।



Financial Emergency

- The salaries and allowances of government officials are anticipated to be reduced in the event of a financial emergency. India has not yet had a financial emergency. Although it was anticipated that there may be financial turbulence in 1991. Without needing to proclaim a state of emergency, the Indian government handled the problem quickly.

वित्तीय आपातकाल

PG Reforms

- वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सरकारी अधिकारियों के वेतन और भत्ते कम होने का अनुमान है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। हालाँकि यह अनुमान लगाया गया था कि 1991 में वित्तीय अशांति हो सकती है। आपातकाल की स्थिति घोषित किए बिना, भारत सरकार ने समस्या को तुरंत संभाल लिया।



GS/ GK का महासंग्राम



Q. 1 Which Articles of the Indian Constitution contain the Emergency Provisions?

✓ भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं?

20

Art+352

↳ राष्ट्रीय आपातकाल

Art+356 → संवैधानिक
आपातकाल

Art+360 → वित्तीय
आपातकाल

(a) Article 350-360

(b) Article 352-360

(c) Article 342-350

(d) Article 362-370



Q.2 Which Article of the Indian Constitution contains the provisions of National
/ Emergency?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान हैं?

20

द्वितीय आपातकाल

राष्ट्रपति
शासन

(a) Article 352

(b) Article 356

(c) Article 360

(d) Article 362



Q 3. Who is empowered to declare National Emergency under Article 352?
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है?

20

Cabinet की लिस्ट सिफ़ा (राष्ट्रपति)
राष्ट्रपति Declare करता है

- (a) Parliament
- (b) Prime Ministers
- (c) Council of Ministers
- (d) President



GS/ GK का महासंग्राम



Q 4. Which of the following are the grounds on which National Emergency can be declared?

1. External aggression → बाह्य आक्रमण
2. Internal disturbances → आतंकवादी
3. Armed rebellion → हथियार विद्रोह
4. Communal riots → साम्प्रदायिक दंगे

Select the correct option from the codes given below:

(a) Only 1 & 2

(b) Only 1 & 3

(c) Only 3 & 4

(d) Only 1 & 3

20



GS/ GK का महासंग्राम



Q.5 On which basis the President cannot declare National Emergency?

✓ किस आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते?

20

① War or External Attack

② Armed Rebellion

- ✓ a) War ✓
- ✓ b) External Attack ✓
- ✓ c) Threat to Internal Peace
- ✓ d) Armed Rebellion ✓



Q.6 Proclamation of emergency must be approved by both the houses of
/ parliament within?

आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए?



- a) 1 month
- b) 2 months
- c) 6 months
- d) 1 year



GS/ GK का महासंग्राम



- Originally, it was 2 months but reduced to 1 month by the 44th amendment act of 1978.
- Once approved, it will be valid for six months and can be extended to an infinite period with the approval of parliament every six months.

• मूल रूप से, यह 2 महीने था लेकिन 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटाकर 1 महीना कर दिया गया।

• एक बार मंजूरी मिलने के बाद, यह छह महीने के लिए वैध होगा और हर छह महीने में संसद की मंजूरी के साथ इसे अनंत अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

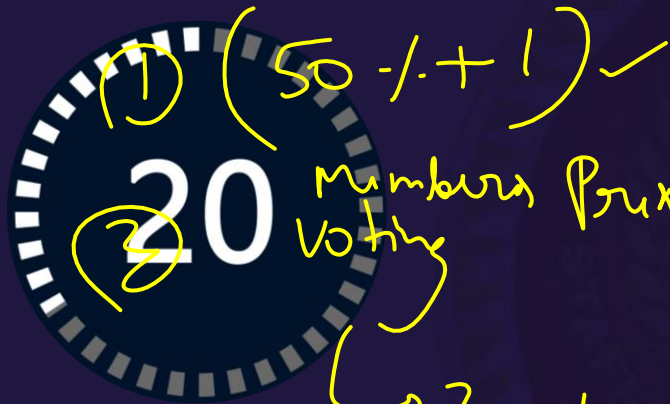


GS/ GK का महासंग्राम



Q.7 Which type of Majority is needed to pass the emergency resolution in Parliament?

✓ आपातकालीन प्रस्ताव पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? संसद?



- ✓ a)
- ✓ b)
- ✓ c)
- ✓ d)

Simple Majority

Special Majority

Special majority and approval by half of the states' assembly

Absolute majority



GS/ GK का महासंग्राम



- Special Majority [majority of total membership and 2/3rd of the members of the present and voting;
- Earlier, only a simple majority was needed. A special majority provision was added by the 44th amendment act of 1978. It was also added in this amendment act that the president must revoke the emergency if the Lok Sabha disapproves.

- ✓ विशेष बहुमत [कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 ;
- ✓ पहले सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती थी. 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक विशेष बहुमत का प्रावधान जोड़ा गया। इस संशोधन अधिनियम में यह भी जोड़ा गया कि यदि लोकसभा इसे अस्वीकार करती है तो राष्ट्रपति को आपातकाल को रद्द करना होगा।



GS/ GK का महासंग्राम



Q.8 Article 358 deals with?

अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है?

20 *fr/w*

- a) Suspension of fundamental rights guaranteed by article 19
- b) Suspension of fundamental rights other than Articles 19, 20, and 21
- c) Both of the above
- d) None of the above



GS/ GK का महासंग्राम



- Article 358 deals with Suspension of fundamental rights guaranteed by article 19.
- Article 359 deals with the Suspension of fundamental rights other than Articles 19, 20, and 21.
- अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।
- अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 19, 20 और 21 के अलावा मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।



GS/ GK का महासंग्राम



Q.9 National emergency was not declared in which of the following year?
निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया था?



- (a) 1962
- (b) 1971
- (c) 1975
- (d) 1999



GS/ GK का महासंग्राम



Q.10 Which of the following judgment held that the proclamation of national emergency can be challenged in a court on the ground of malafide or others.
निम्नलिखित में से किस फैसले में कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावना या अन्य आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

20

- a) Champakam Dorairanjan case (1951)
- b) Golaknath Case (1967)
- c) Kesavananda Bharti case (1973)
- d) Minerva Mills case (1980)



GS/ GK का महासंग्राम



Q.11 Who can make laws on any matter in the State List for implementing the international treaties, agreements or conventions?

अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून कौन बना सकता है?

20

- a) The Parliament
- b) The Council of Ministers
- c) The Prime Minister
- d) The Vice President



GS/ GK का महासंग्राम



- The Parliament of India is empowered to make laws on any matter in the State List for implementing the international treaties, agreements or conventions. The provision enables the Central government to fulfill its international obligations and commitments.
- भारत की संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है।